शिकायतें आई हैं कि वहां के जो रहने वाले ठेकेदार हैं उनको ठेका न दे कर बाहर के लोगों को ठेके दिये जा रहे हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी शिकायतें आई हैं कि नहीं ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : जहां तक मेरी मिनिस्ट्री का ताल्लुक है शुरू से ले कर आखिर तक शिकायतें ही शिकायतें होती हैं मगर जांच करने पर सही बहुत कम निकलती हैं ।

Shri Panigrahi: The question is whether complaints have been received by the Ministry that the local contractors are not being given preference

Mr. Speaker: That is the question of Seth Achal Singh

Shri Mehr Chand Khana: Suppose I am working in Madhya Pradesh or Orissa If it is possible to have a local contractor I would like to help him and gain his sympathy and support But I am not going to give any contract to him if the article does not come up to the normal standard

Shri Hem Barua *rose*—

Mr Speaker: The hon Member comes from Assam

Shri Hem Barua. I am interested in Dandakaranya also

Mr Speaker: I cannot give an opportunity to every one of the 500 Members on every subject, because time is limited I will call him twice when Assam comes

Shri Hem Barua: This encourages regionalism

Mr Speaker Asking why local contractors are not given preference also is regionalism Next question

"भारत १९५८" जैसे प्रकाशनों के हिन्दी संस्करण

*१८१६ श्री भक्त दर्शन . क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ·

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ समय से "भारत १९५८" जैसी जो पुस्तकें प्रतिवर्ष प्रकाशित की जा रही हैं उनके अंग्रेजी संस्करण तो समय पर प्रकाशित हो जाते हैं, किन्तु उन के हिन्दी संस्करणों का प्रकाशन कई महीने की देरी के बाद होता है ,

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं , और

(ग) ऐसी पुस्तकों के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों को एक साथ प्रकाशित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री के संसद-सचिव (श्री अ० च० जोशी): (क) से (ग) इस बात का खेद है कि "भारत १९५८" तथा 'ग्यारहवां वर्ष' के अंग्रेजी संस्करण के प्रकाशन के बाद हिन्दी संस्करण के प्रकाशन में कुछ देर हुई है। कुछ हद तक यह अनिवार्य भी है क्योंकि अंग्रेजी सामग्री के तैयार हो जाने के बाद ही उस का हिन्दी में अनुवाद किया जाता है ।

यह इस समय सम्भव नहीं है कि सारी सामग्री मूलतः हिन्दी में तैयार की जाये, क्योंकि इसके लिये बहुत खर्चा होगा । अंग्रेजी तथा हिन्दी के प्रकाशन में समय के इस अन्तर को कम करने के लिये यह प्रयत्न किया जा रहा है कि अंग्रेजी में एक अध्याय तैयार हो जाये तुरन्त ही उस का हिन्दी में अनुवाद किया जाये ।

Some Hon Members The English answer may be read

Mr Speaker: Yes

Shri A. C Joshi: (a) to (c) There has been a regrettable time lag between English and Hindi editions of "India 1958" as well as the "Eleventh Year" This is to some extent unavoidable as the material in English has to be translated into Hindi after it is ready

It is not possible at present to prepare all the material originally in Hindi as it would be too costly Efforts

are being made to reduce this lag considerably by taking up the translation as soon as the manuscript of each chapter in English is ready.

श्री भक्त दर्शन क्या शासन ने इस बात पर विचार किया है कि जिस तरीके से संविधान का अंग्रेजी और हिन्दी में समानान्तर अनुवाद हुआ है उस तरह जितने भी महत्वपूर्ण प्रकाशन है, उनका द्वि-भाषी प्रकाशन अथवा 'डिग्लौट' संस्करण एक साथ प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) यह व्यवहार की दृष्टि से सम्भव नही है खासतौर से इस रेफेंस की किताब के बारे में। माननीय सदस्य खुद इस बात को समझेंगे कि जो मैटीरियल आता है वह दो भाषाओ में एक साथ लाना यह हमारे लिये बहुत मुश्किल होगा और मैटीरियल आने के बाद किसी न किसी समय उसका अनुवाद हम को करना ही पडेगा।

श्री भक्त दर्शन क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओ के प्रकाशन केवल देरी में ही प्रकाशित नही होते बल्कि उन्हें अधिक संक्षिप्त करके प्रकाशित किया जाता है, इसलिये क्या ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि कम से कम जितने महत्वपूर्ण प्रकाशन है वे उतने ही वौल्यूम में प्रकाशित किये जाया करे और उनको सक्षिप्त न किया जाया करे ?

डा० केसकर माननीय सदस्य की इनफार्मेशन के लिये मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह हमारा रेफेंस का जो वार्षिक प्रकाशन है यह एक बार पूरी तौर हिन्दी में प्रकाशित किया गया और उसकी ६० फीसदी कापियां अनैर बिके पडी रही और तब से हमको इसे संक्षिप्त कर के प्रकाशित करना पड़ा वरना हम बहुत हर्ष के साथ उसका पूर्ण हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करते।

सेठ गोविन्द दास माननीय मंत्री ने अभी यह कहा कि अलग अलग हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में इस प्रकार का काम करने से बहुत खर्चा पड़ता है, मैं जानना चाहता हू कि इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रकाशन हैं वे जब अनुवाद के रूप में निकलते हैं तब वे इतने महत्व के नहीं होते जितने कि मूल में यदि वे तैयार किये जायें तो हो सकते है। ऐसी हालत में क्या सरकार इस बात पर कोई विचार कर रही है कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रकाशनो के लिये हिन्दी का भी एक अलग विभाग खोल दिया जाये और मूल में इस प्रकार के प्रकाशन हिन्दी में तैयार भी किये जायें ?

डा० केसकर. मैं ने पहले भी कहा कि यह व्यवहार में कठिन है। माननीय सदस्य इस बात से ही समझ सकते है कि गवर्नमेंट आफ इडिया की जितनी स्टेटिक्सकल इनफारमेशन है वह सब इकट्ठी कर के हिन्दी में हम प्रकाशित करते हैं। अब उस इनफारमेशन को उन मिन्ट्रीज मे हिन्दी में तैयार करने के लिये हमको आदेश देना पडेगा जिसको कि वह मानेगी या नही, मै यह नही कह सकता, तो यह सब बातें कुछ समय के बाद होगी लेकिन आज इसको करना शायद व्यवहार की दृष्टि से सम्भव नही मालूम होता।

श्री इजराज सिंह अभी मिनिस्टर महोदय ने बतलाया कि भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालय यह आकडे वगैरह हिन्दी में दे सकेंगे या नही यह उन्हें मालूम नही है। मैं जानना चाहूगा कि क्या हिन्दुस्तान के लोगो ने और खास तौर से सूचना मन्त्रालय के लोगो ने क्या अंग्रेजी में सोचना और विचारना शुरू कर दिया है और हिन्दी अथवा अन्य प्रादेशिक भाषाओ में उन्होंने सोचना विचारना बिलकुल बन्द कर दिया है ? क्या खास दिक्कतें हैं जिनकी कि वजह से गवर्नमेंट आफ इंडिया के दूसरे मन्त्रालय हिन्दी में ऐसा नही कर सकेंगे ?

डा० केसकर इस विषय पर काफी बहस हो चुकी है और इन प्रश्नों का उत्तर इस वक्त संक्षेप में देना हमारे लिये सम्भव नहीं है और किसी अन्य समय विस्तार से इसका जवाब दिया जायेगा।

Shri C D Pande: The hon Minister said that 90 per cent of the books published in Hindi were not sold May I draw his attention to the fact that 90 per cent of the literature supplied free is not read either? So, there should be economy in such publications

Dr Keskar: My hon friend is entirely incorrect I have had occasion to say a dozen times on the floor of this House that all our literature, including publicity literature is sold out and not more than 5 per cent of books are distributed

श्री वाजपेयी क्या यह सच नहीं है कि इस पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण को बेचने के लिये जितना प्रचार किया गया उतना प्रचार हिन्दी संस्करण को बेचने के लिये नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप वह पड़ा रहा ?

डा० केसकर हिन्दी संस्करण को बेचने के लिये अंग्रेजी से दूना प्रयत्न किया गया।

श्री भक्त दर्शन क्या यह आशा की जा सकती है कि "इंडिया १९५९" का जो संस्करण निकलेगा उसका हिन्दी का संस्करण कम से कम एक दो महीने के अन्दर निकाल दिया जायेगा ?

Mr. Speaker: This is suggestion for action.

डा० केसकर यह जल्दी निकले इसकी चिन्ता हमको भी है और व्यावहारिक रूप में हम जितनी जल्दी कर सकेंगे जरूर करेंगे।

Cotton Merchants Association Raichur (Mysore)

*1817 **Shri Shivananjappa:** Will the Minister of Commerce and Industry be pleased to state

(a) whether business in the Raichur Cotton Market, the biggest in the Mysore State, came to a standstill recently following a decision taken by the Cotton Merchants Association to suspend business, and

(b) if so, the reasons thereof?

The Minister of Commerce (Shri Kanungo): (a) Yes, Sir The business remained suspended between the 3rd and 12th March, 1959.

(b) The Cotton Merchants Association decided to suspend business as a protest against the open bidding system which was introduced by the Marketing Officer to the Mysore Government

Shri Shivananjappa May I know whether the Government have taken any steps to look into the grievances of these marchants?

Shri Kanungo: There is no grievance as such, because the matter was settled and the market was opened on the 12th March As far as the internal organisation of the market is concerned, it is the responsibility of the marketing organisation of the State Government

Shri Shivananjappa: May I know whether the business has resumed now?

Shri Kanungo: It was resumed on the 12th March

Shri Basappa: May I know the quantity of cotton held up due to the stoppage of trade and the amount of loss the cotton growers have suffered?

Shri Kanungo: We have no figures with us because the control and the running of the markets is the responsibility of the State Government But, obviously, there must have been